LOK SABHA

Friday, May 28, 1971/Jyaistha 7, 1893 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

मार्च 1971 में इंडियन एयरलाइन्ज में की गई तालाबन्दी के फलस्वरूप हुई क्षति

*121 **श्री जगन्नाथराव जोशी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत मार्च में इंडियन एयरलाइन्ज में तालाबन्दी कितने दिन तक जारी रही ,

(ख) इस अवधि में कर्मचारियों तथा सरकार की कितनी क्षति हुई , और

(ग) इस तालाबन्दी के प्रमुख कारण क्या थे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से क्या ऐहतियाती कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 13 मार्च, 1971 से 28 मार्च, 1971 तक ।

(ख) कर्मचारियों को वेतनों में लगभग 47 लाख रुपये की और कारपोरेशन को 124 लाख रुपये की हानि हुई ।

(ग) कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या द्वारा 'नियमानुसार कार्य और धीरे चलो' जैसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके अपनाने के परिणामस्वरूप अन्तर्देशीय विमान सेवाएं स्थगित हो गयी और बहुत से विमान भूमिस्थ किये जाने पड़े । इस परिस्थितियों में क्यों कि एयरलाइन को चलाना असम्भव हो गया, प्रबन्धक-वर्ग ने तालाबंदी की घोषणा कर दी ।

27 मार्च को चार प्रमुख संघों के साथ एक समझौता हो गया जिसके अनुसार यह तय किया गया कि तालाबन्दी समाप्त की जाए और विमान सेवाएं पुन सामान्य रूप से चालू की जाये। जैसा कि मैंने इस सदन को आश्वासन दिया था उसका अनुसरण करते हुए सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो इंडियन एयरलाइन्स की संगठनात्मक एवं प्रशासकीय रचना तथा उसके प्रबन्धक और कर्मचारी वर्गों के आपसी संबंधों की जांच करेगी, और विशेषत उसकी कार्मिक नीतियां एवं कार्य-प्रणालियों की दृष्टि से सरकार को सिफारिशें प्रदान करेगी ।

श्री जगन्नाथराव जोशी : जवाबों जैट का जवाब जरूर आया है लेकिन लगता है कि यह विमान सेवाएं बैलगाड़ी की मनोवृत्ति से चलाई जा रही हैं । विमान कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है और इस बात को लेकर मैनेजमेन्ट के साथ जो वार्ता चल रही थी और एयरलाइंज यूनियन की एक्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग 13 मार्च को दिल्ली में होने वाली थी ऐसी स्थिति में 13 मार्च को ही मैनेजमेन्ट द्वारा लौक आउट डिक्लेयर कर देना यह कर्मचारियों के मुंह पर तमाचा मारना है । हाल के संख्या-

अधि चुनाव में सत्ताधारी दल को दो तिहाई बहुमत मिलने के बाद कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना कहां तक उचित व सही है यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ ?

डा० कर्ण सिंह : चुनावों के साथ इस तालाबन्दी का कोई सम्बन्ध नहीं है। जैसा कि मैंने अपने मूल उत्तर मे बतलाया है स्थिति ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बन गई थी कि तालाबन्दी करने के सिवाय उस समय कोई और तरीका ही नही था लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि स्थिति इतनी निराशाजनक नही है जितनी कि माननीय सदस्य ने बतलाई है। मुझे आशा है कि अब स्थिति सुधरनी जायगी और वास्तव मे जो जैट एज आई है उसके अनुसार ही यह हमारी विमान सेवाएं चलेंगी।

श्री जगन्नाथराव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि मैनेजमेन्ट के साथ जो निगोशिएशंस चल रही थी, चर्चा चल रही थी तो वह वार्ता ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी कि उससे कोई अच्छा नतीजा निकल सकता था और जब इस पर विचार करने के लिए इण्डियन एयरलाइन्स यूनियन की एक्जीक्युटिव कमेटी की मीटिंग यहाँ दिल्ली मे 13 मार्च को होने वाली थी तो ऐसी स्थिति मे 13 मार्च को सुबह ही से अर्थात् उसके 7 घंटे पहले से ही लौक आउट मैनेजमैंट द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया और जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियो को वेतनो में लगभग 47 लाख रुपये की हानि उठानी पडी है तो आखिर इस के लिये कौन जिम्मेदार है यह मैंने सवाल किया था ?

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि उस समय तक अर्थात् 13 मार्च तक कर्मचारियों ने जो वह "नियमानुसार कार्य" और "धीरे चलो" जैसे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके अपनाये थे उसके परिणाम स्वरूप हमारी विमान सेवाएँ स्थगित हो गयी थीं और ऐयरलाइन को चलाना असम्भव हो गया था तब और कोई चारा न रहने के कारण मजबूर होकर प्रबन्धक-वर्ग को तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। हालत उस समय हमारी ऐसी हो गयी थी कि सारे देश में हमारी सेवाएँ नष्ट-भ्रष्ट हो गई थीं और किसी को पता नहीं चल रहा था कि कोई विमान जायेगा भी या नहीं जायेगा। जब ऐसी बुरी स्थिति हो गयी तो सिवाय तालाबंदी करने के हमारे पास और कोई चारा नही रह गया था और इसलिए उसे करना पड़ा। वैसे हमारे लिए इसे करना कोई प्रसन्नता की बात नही थी और ऐसा कोई अपने मन से नही करना चाहता है और मजबूरन हमें वैसा करना पड़ा। मुझे आशा है कि वैसी स्थिति फिर कभी हमारे देश मे नही आयेगी।

श्री जगन्नाथराव जोशी : कर्मचारियों के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ था दो साल पहले वह खत्म हो गया और उस समय कोई नया एग्रीमेंट किया जाता जैसे कि वह नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्युनल ने सिफारिशें दी और खोसला कमिशन ने कर्मचारियों के बारे में अपनी सिफारिशें दी तो शासन ने उनको क्यों नही स्वीकार किया और उस का क्या कारण है यह मैं जानना चाहता हूं ?

डा० कर्ण सिंह : उस के आधार पर कर्मचारियों के साथ वार्ता चल रही है। जो पुराने एग्रीमेंट थे वह अब समाप्त हो गये। उसके बाद बातचीत आरम्भ हुई थी। मुझे खेद है कि उस समय वह नया एग्रीमेंट नहीं हो सका। अगर वह हो सकता तो ऐसी स्थिति शायद पैदा न होती लेकिन वह खोसला ट्राइब्युनल को मद्देनजर रखते हुए ही अब आगे बातचीत चल रही है। वैसे अभी भी नया एग्रीमेंट नहीं हुआ है लेकिन कर्मचारियों के साथ अब बातचीत हो रही है

और मुझे आशा है कि सारी स्थिति सुधर जायेगी ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : खोसला कमिशन के बारे में यह कहा गया था कि उसकी सिफारिशें.....

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । आई ऐम सौरी ।

SHRI S. M. KRISHNA : Is it not a fact that the strike and go-slow attitude and the subsequent lock-out were largely due to the controversy that was raised about Avro 748 ? Has a decision been taken about the air-worthiness of Avro or safety of Avro ? Secondly, what exactly is the load that Avros are carrying now ? The stipulated load that an Avro is capable of carrying is 44,500 lbs.

MR. SPEAKER : The question is about lock-outs.

SHRI S. M. KRISHNA : The whole controversy was around Avro 748. What is the load that Avros are carrying ?

DR KARAN SINGH : I think the hon. Member is not correct when he says that the lock-out was connected directly with the Avros. This lock-out was the result the of action which the IATA took, not the pilots ; that was an earlier situation which developed, if you will remember, towards the end of December. Then I may say that we have set up a committee to look very carefully into the air-worthiness of the Avros and that committee's work is proceeding. We expect a report within the next two months or so. After that report is received we will very carefully look into the recommendations and if anything is necessary to be done we will do that.

SHRI INDRAJIT GUPTA : The hon. Minister has just now reminded us that this lock-out did not arise out of any dispute with the pilots. During the period of the lock-out certain skeleton services were operated, or tried to be operated. I want to know from him whether it is a fact or not that these skeleton services were operated by the executive pilots, who altogether probably number only 15 or so in the Indian Airlines, whereas the regular pilots, the Commercial Pilots' Association, have issued a statement saying that since this dispute was not with them they were prepared to offer their services to run the skeleton services in the interests of the public. When there was no dispute with these pilots, why were they not permitted to operate the skeleton service and why only the executive pilots were utilized ?

DR. KARAN SINGH : Before I answer the question I must say that although the pilots were not directly concerned with this, there was a dispute earlier and it was a continuing dispute resulting from the December situation. But the hon. Member's point is quite simple. When a lock-out is declared, you lock-out the entire staff. It is not possible to lock-out selectively that you lock-out the air hostesses and leave out the pilots. When you lock out the entire staff are covered by that lock-out. But the executive pilots, being employees of the management, are not effected by the lock-out. Therefore, the only pilots we could possibly use were the executive pilots.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The hon. Minister has stated that a committee has been set up for the purpose of going into the question of organisation of the Indian Airlines. Will that committee go into the question of the feasibility of adopting a policy of workers' participation in the management so that in future the differences between the management and the employees can be narrowed down ?

DR. KARAN SINGH : The Committee, will recommend specially with regard to the personnel policy. That can certainly include workers' participation. But I may mention that the broader question of workers' participation in the

public sector undertakings is separately under the active consideration of the Government.

Development of Kovalam Beach In Kerala as a Major Tourist Centre

*122. SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN : Will the Minister of TOURISM AND CIVIL AVIATION (PARYATAN AUR NAGAR VIMANAN MANTRI) be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the development of Kovalam beach in Kerala at a major tourist centre ;

(b) the estimated cost of the Kovalam project ;

(c) the expenditure incurred so far ; and

(d) how long it will take to complete the project ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (PARYATAN AUR NAGAR VIMANAN MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (DR. SAROJINI MAHISHI) : (a) The plans of the cottages, the beach service centre and the hotel have been approved, and construction work with commence shortly.

(b) The total estimated cost of the project is Rs. 221.58 lakhs.

(c) An expenditure of Rs. 16.25 lakhs has been incurred so far.

(d) It is hoped to complete the project during the Fourth Plan period.

SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN : I would like to know from the hon. Minister whether the Government have under consideration a proposal to extend the line of Boeing service upto Trivandrum which will pave the way for attraction of foreign tourists and can thus earn foreign exchange. Secondly, I would like to know whether the Government have any proposal for the development of other tourist centres in Karala and, if so, the details thereof.

DR. SAROJINI MAHISHI : As regards the first question, the services of Boeing are going to be extended to Trivandrum by 15th October. As regards the second question, there are a number of projects which have been taken up by the Central Government. A number of improvements and expansion accommodation have taken place at Aranga Niwas at Thekkady and also at Muskat Hotel. A Youth Hostel is going to be constructed at Trivandrum soon. A jetty construction was also financed in Kerala ; celebrations of Onam festival was subsidised.

Life Insurance Corporation's Investment in Public and Private Sector

*123. SHRI S. R. DAMANI : Will the Minister of FINANCE (VITTA MANTRI) be pleased to state :

(a) the policy followed by the Life Insurance Corporation for investment in the public sector and private sector industrial undertakings ; and

(b) the amounts invested so far in each sector and the yields on such investments ?

THE MINISTER OF FINANCE (VITTA MANTRI) (SHRI YESHWANTRAO CHAVAN) : (a) and (b). A statement giving the information asked for is laid on the Table of the House.